

न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 43/2022 आवंटन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बनाम भीमराज, नन्दकिशोर, बिना, फुलवती, अनिता पिता
बिजौलिया जिला भीलवाड़ा रामलाल यादव निवासी सलावटिया तहसील
बिजौलिया

—प्रार्थी

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित -

1. राजकीय अधिवक्ता - प्रार्थी की ओर से



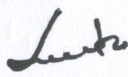
निर्णय

दिनांक 26.05.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरुद्ध विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम आरोली की आ.न. 1158/978 रकबा 0.4856 हैक्ट. भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटि के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटि (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटि का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिनांक 21.11.2022 को दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी के सम्मन तामील में विपक्षी की सकुनत गलत होना अंकित किया है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि विपक्षी के सम्मन की तामील में विपक्षी की सकुनत गलत होना अंकित किया है। इस प्रकार प्रार्थी तहसीलदार बिजौलिया ने सही

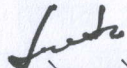

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

सकुनत पेश नही कर विपक्षी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) प्रस्तुत किया है, जो नियम विरुद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) अस्वीकार किया जाना युक्तियुक्त हैं।

तहसीलदार बिजौलिया द्वारा सही सकुनत रिपोर्ट मय सम्मन भी पेश नही किये गये। जबकि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिनांक 21.11.2022 से ही पंजीबद्ध चला आ रहा है। प्रकरण में काफी समय व्यतीत होने पर भी प्रार्थी ने विधिवत प्रक्रिया नही अपनायी है, इस प्रकार तहसीलदार बिजौलिया ने न्यायालय का श्रम व समय अनावश्यक जाया किया है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजौलिया को प्रेषित की जावे। तहसीलदार बिजौलिया पूर्ण दस्तावेज की जांच कर प्रकरण नये सिरे से न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर
भिलाई